

Lok Sabha seventeenth lok sabha

Fourth Session

30th September 2020

1. प्रश्नकाल (परीक्षण के लिए)
2. बजट अनुमान - प्रस्तुति (परीक्षण के लिए)

(1)

प्रस्तावना

भारत के संविधान का यह संस्करण समय-समय पर संसद द्वारा संशोधित भारतीय संविधान के पाठ को पुनः प्रस्तुत करता है। संसद द्वारा और संविधान (एक सौ और चौथा संशोधन) अधिनियम, 2019 सहित सभी संशोधन इस संस्करण में शामिल किए गए हैं। पाठ के नीचे के फुट नोट्स संविधान संशोधन अधिनियमों को इंगित करते हैं जिसके द्वारा ऐसे संशोधन किए गए हैं। संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश, 2019 APPENDIX - I संदर्भ के लिए प्रदान किया गया है। संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 और संविधान (अस्सी-आठवां संशोधन) अधिनियम, 2003 से संबंधित संवैधानिक संशोधनों का पाठ, जो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, पाठ में उपयुक्त स्थानों पर प्रदान किए गए हैं। या अन्यथा फुटनोट में। इन संशोधनों का पाठ संदर्भ के लिए APPENDIX-II और APPENDIX - III में प्रदान किया गया है। भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच अधिग्रहित और हस्तांतरित क्षेत्रों के विवरण वाले संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, को APPENDIX - IV में प्रदान किया गया है। नई दिल्ली; डॉ। जी। नारायण राजू, 9 दिसंबर, 2020. भारत सरकार के सचिव।

(i) यूनिअन एंड टेरिटरी

- (2) नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना। - संसद संघ में कानून स्वीकार कर सकती है, या नए राज्यों को ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थापित कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझती हैं।

3.

नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन। —

संसद कानून द्वारा हो सकता है

- (1) (ए) किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को एकजुट करके या किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बना सकते हैं; (बी) किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि; (ग) किसी राज्य का क्षेत्र कम हो जाएगा; (घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन; (() किसी राज्य का नाम बदलो: 4 [बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश को छोड़कर संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाएगा और जब तक, विधेयक में निहित प्रस्ताव राज्य के किसी भी क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित नहीं करता है, विधेयक में है राष्ट्रपति द्वारा उस अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उस राज्य के विधानमंडल को संदर्भित किया जाता है,

जैसा कि संदर्भ में निर्दिष्ट किया जा सकता है या आगे की अवधि के भीतर हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है और अवधि इतनी निर्दिष्ट या अनुमत हो गई है।] 6 [स्पष्टीकरण। - इस लेख में, खंड (ए) से (ई) में, State territory में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, लेकिन अनंतिम में, State में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। स्पष्टीकरण ॥ - खंड (क) द्वारा संसद द्वारा प्रदत्त शक्ति में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति शामिल है।]

(Shri Om Birla),

|

(SNEHLATA
SHRIVASTAVA),

|
